वेबसाईट : www.abvp.org पंजिकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय– 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष :(022) 24306321 / 24378866 फैक्स :24313938 ई–मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 04 अगस्त 2021

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

अभाविप प्रतिनिधि मण्डल ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेडी को सौंपा ज्ञापन

अभाविप के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने जनजातीय छात्रों के विभिन्न विषयों पर अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को 14 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी को भी ज्ञापन सौंपते हुए कला एवं सांस्कृतिक विषयों की चर्चा की तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान से मिलकर जनजातीय समाज के विभिन्न सामाजिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर चर्चा की।

केंद्रीय संस्कृति मंत्री को ज्ञापन में देश में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयों की संख्या बढ़ाने, प्राथमिक विद्यालयों में नाट्य गतिविधि को प्रारम्भ करना एवं लुप्त हो रही लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने जैसी प्रमुख माँग की।

जनजातीय आयोग को अभाविप ने अपने मांग पत्र में जनजाति क्षेत्रों में स्कूली एवं उच्च शिक्षा संबंधी सभी रिक्त पदों की भर्ती,प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मार्गदर्शन केंद्र, जनजातीय आस्था केंद्रों को जनजातीय राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मान्यता देने एवं उनके विकास की योजना बनने,अनुसूचित जनजाति लंबित प्रकरणों का जल्द जल्द से समाधान किया जाए आदि मांगों को सम्मिलित किया।

अभाविप का मानना है कि जनजातियों क्षेत्रों की संस्कृति के संरक्षण के लिए जनजातीय संरक्षण नीति बनाई जाए जिससे इनकी संस्कृति ,लिपि, बोली, भाषा संरक्षित हो सके तथा अभाविप की मांग है कि जनजातीय क्षेत्र के युवाओं के रोजगार प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा इंटर्नशिप की योजना की जाए।

राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा, "देश के अलग-अलग हिस्सों में विशेषतः जनजातीय क्षेत्र में आने वाली शैक्षणिक तथा सामाजिक समस्याओं को एकत्र कर हमने अपना मांगपत्र अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान को सौंपा तथा माननीय अध्यक्ष से जल्द से जल्द इन मांगों पर विचार करने को कहा। कला के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए भी ज्ञापन संस्कृति मंत्री को दिया गया एवं जल्द कार्यवाही का आश्वासन मिला है।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री सुमित पाण्डेय द्वारा जारी की गई है।)